राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 263

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, शनिवार, 29 फरवरी 2020

www.jagran.com

पृष्ठ 16

चोट की वजह से इशांत शर्मा दूसरे टेस्ट से बाहर

>> 14

सरोकार

खिलखिलाने लगी 45 साल से मृत लखनदेई नदी

सीतामढ़ी : नदी को नवजीवन देने में जनता और प्रशासन का परिश्रम रंग लाया। उपेक्षा की वजह से लक्ष्मणा नदी (लखनदेई) 45 सालों से मृत पड़ी थी। सकारात्मक पहल हुई तो खिलखिलाने लगी। (पेज-10)

जागरण विशेष

दोगुना कर दिखाया टैक्स कलेक्शन, राज्य में अव्वल

भोपाल : जिसे लूप लाइन माना, उसे महिलाओं ने सबसे ज्यादा राजस्व देने वाली जगह बना दिया। भोपाल वाणिज्यिक कर संभाग के सर्किल-4 की सफलता की कहानी, जहां 90 फीसद अधिकारी और कर्मचारी महिलाएं हैं। (पेज-10)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

निर्भया के दोषी पवन ने दाखिल की क्यूरेटिव याचिका

नई दिल्ली : दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म कांड के दोषी पवन गुप्ता ने फांसी से बचने के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। फांसी की तारीख नजदीक आती देख पवन ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दाखिल कर मृत्युदंड को चुनौती दी है।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 6

पुलवामा के गुनाहगारों को पनाह देने वाला गिरफ्तार

श्रीनगर : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने शुक्रवार को पुलवामा के गुनहगारों को घर में पनाह देने वाले और हमले की साजिश में शामिल रहे जैश-ए-मुहम्मद आतंकी शाकिर अहमद को गिरफ्तार कर लिया है।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

सीरिया के हवाई हमले में तुर्की के 33 सैनिकों की मौत

अंकारा : सीरिया के इदलिब प्रांत में गुरुवार को हवाई हमले में तुर्की के 33 सैनिकों की मौत हो गई। इस पर तुर्की ने सीरियाई शासन के ठिकानों पर हमला बोल दिया। इस कार्रवाई में सीरिया के 16 सैनिकों के मारे जाने की खबर है।

आजकल ▶ पृष्ठ 16

नासा ने पृथ्वी जैसी दुनिया समेत 17 नए ग्रह खोजे

टोरंटो : नासा की केप्लर सैटेलाइट ने 17 नये ग्रहों की खोज की है। इसमें से एक पृथ्वी जैसा रहने योग्य दुर्लभ ग्रह भी शामिल है। यह सभी ग्रह सितारों के ऐसे 'संभावित जीवन वाले जोन' में मिले हैं जहां पथरीले ग्रहों में तरल रूप में जल मिलने की संभावना है।

असली टेस्ट
दूसरा टेस्ट
भारत vs न्यूजीलैंड
सुबह 4:00 बजे
स्थान: क्राइस्टचर्च
प्रसारण: स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क

दंगाइयों की पहचान में जुटी पुलिस, 148 केस दर्ज, 630 गिरफ्त में

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- आइबी जवान की हत्या मामले में पार्षद के घर से मिले सुबूत
- जीटीबी पहुंचे चार और शव, हिंसा में मरने वालों की संख्या 42 पहुंची

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के खजूरी स्थित पार्षद ताहिर हुसैन के घर के बाहर से साक्ष्य जुटाते क्राइम ब्रांच और फोरेंसिक जांच टीम के सदस्य। हरीश कुमार

सांप्रदायिक हिंसा से झुलस रही दिल्ली के कुछ इलाकों में शुक्रवार को भी तनाव बरकरार रहा और छिटपुट टकराव सामने आए। हिंसा थमने के बाद पुलिस ने दंगाइयों पर शिकंजा कस दिया है। 148 केस दर्ज करने के साथ ही पुलिस अब तक 630 को या तो गिरफ्तार कर चुकी है या हिरासत में ले चुकी है। आइबी (इंटेलीजेंस ब्यूरो) के जवान अंकित शर्मा की हत्या मामले में आरोपित आम आदमी पार्टी से निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन की तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। डीसीपी जॉय टर्की के नेतृत्व में पहुंची क्राइम ब्रांच और एफएसएल (फोरेंसिक साइंस लेबोरेट्री) की टीम ने पार्षद के घर से दंगे से जुड़े कई अहम सुबूत जुटाए हैं। पत्थर, पेट्रोल बम, तेजाब के पाउच और गुलेल के नमूने उठा लिए गए हैं। उस स्थान से भी साक्ष्य जुटाए गए जहां से अंकित का शव बरामद हुआ था। जांच टीमें ड्रोन व सीसीटीवी फुटेज से सुबूत जुटा रही हैं। दंगाइयों की पहचान के लिए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम की मदद ली जा रही है। इस बीच, चार और शव मिलने से हिंसा में मृतकों की संख्या बढ़कर 42 हो गई है।

जुमे की नमाज होने की वजह से शुक्रवार को सुबह आठ से दोपहर दो बजे तक और शाम को चार बजे से आठ बजे तक कर्फ्यू में छूट दी गई। कड़ी सुरक्षा में सीलमपुर, जाफराबाद, नूर-ए-इलाही, ब्रह्मपुरी रोड, घोंडा, कर्दमपुरी, करावल नगर, मुस्तफाबाद, चमन पार्क समेत हिंसाग्रस्त इलाकों में नमाज अदा की गई। मौजपुर, घोंडा, यमुना विहार समेत कई इलाकों में जनजीवन पटरी पर लौटता हुआ दिखाई दिया, लेकिन चांद बाग, शिव विहार, बृजपुरी, चमन पार्क, नूर-ए-इलाही समेत कई जगहों पर तनाव दिखा। यहां दुकानें भी नहीं खुलीं।

जली कारों से लोहा निकाल रहे युवक को मार डाला : शुक्रवार सुबह शिव विहार के बाबू नगर में कूड़ा बीनने वाला युवक पार्किंग में जली कारों से लोहा निकाल रहा था। कुछ लोगों ने संदेह होने पर उसकी पिटाई कर दी और फरार हो गए। बाद में उसकी मौत हो गई। शिव विहार से ही एक अन्य युवक का शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान नहीं हो पाई है। गोकलपुर नाले से मिले दो शवों की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। हिंसा में घायल एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। (पेज-2 भी देखें)

सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर

उपराज्यपाल अनिल बैजल ने भी हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा किया। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता मंदीप रंधावा ने बताया कि पुलिस सोशल मीडिया पर नजर रख रही है। आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

एसएन श्रीवास्तव को पुलिस आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार

नई दिल्ली : दिल्ली में दंगों के बीच बीते मंगलवार को वरिष्ठ विशेष आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) बनाए गए आइपीएस सच्चिदानंद श्रीवास्तव एक मार्च से पुलिस आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगे। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। श्रीवास्तव अमूल्य पटनायक की जगह लेंगे, जो 37 महीने तक यह जिम्मेदारी संभालने के बाद शनिवार को सेवानिवृत्त होंगे। पटनायक का कार्यकाल 31 जनवरी तक ही था, लेकिन विधानसभा चुनाव की वजह से उन्हें एक महीने का सेवा विस्तार दिया गया था। दोनों ही यूटी (संघीय क्षेत्र) कैडर के 1985 बैच के आइपीएस हैं। (पेज-5)

शेयर बाजारों में 'ब्लैक फ्राइडे'

कोरोना की दहशत ▶ सेंसेक्स 1,448 अंक गिरा, इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी गिरावट

निवेशकों को लगी करीब 11 लाख करोड़ रुपये की चपत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

देश-विदेश के अर्थशास्त्रियों की ओर से आशंका जताई जा रही थी कि कोरोना वायरस से दुनिया को उतना नुकसान नहीं होगा, जितना इसके आर्थिक असर से होगा। शुक्रवार को यह बात सच साबित नजर आई जब दुनिया के सभी प्रमुख देशों की इकोनॉमी को कोरोना से भारी नुकसान होने की आशंका से एशिया, यूरोप और अमेरिका के प्रमुख शेयर बाजारों में कोहराम बच गया।

बीएसई का 30 शेयरों वाला प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट का शिकार हुआ। सेंसेक्स में 1,448.37 अंकों (3.64 फीसद) की गिरावट हुई जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के 50 शेयरों वाले प्रमुख सूचकांक निफ्टी में भी 431.55 अंकों (3.71 फीसद) की गिरावट दर्ज की गई। दिन के कारोबार के आखिर में सेंसेक्स 38297.29 पर और निफ्टी 11201.75 पर बंद हुए। इन दोनो बाजारों में शेयर निवेशकों को एक ही दिन में तकरीबन 11 लाख करोड़ रुपये का चूना लगा। सेंसेक्स में इससे पहले 24 अगस्त, 2015 को 1,624.51 अंकों की गिरावट दर्ज की गई थी। शुक्रवार की गिरावट का आलम यह रहा कि किसी भी सेक्टर में निवेशकों को राहत नहीं मिली और इससे भी चिंताजनक बात यह है कि आने वाले दिनों में मंदी का ऐसा माहौल देखने को नहीं मिलेगा, इसका आश्वासन देने वाला कोई नहीं है। बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी समेत दुनियाभर के अधिकतर शेयर बाजार वर्ष 2008 में वैश्विक आर्थिक मंदी के बाद की सबसे बड़ी गिरावट का शिकार हुए।

शुक्रवार के हालात के लिए मोटे तौर पर दूसरे देशों से आए भय के संकेत हैं। कोरोना वायरस के अमेरिका समेत यूरोपीय देशों में पहुंच जाने के बाद इसके वैश्विक अर्थव्यवस्था के ज्यादा प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। अमेरिका का डाऊ जोन्स बाजार 2008 की वैश्विक मंदी के बाद सबसे बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ सिओल, सिंगापुर, जापान व चीन के शेयर बाजार ने भी ऐतिहासिक गिरावट देखी। यूरोप के भी तकरीबन सभी शेयर बाजारों में गिरावट रही। ये सभी शेयर बाजार एकदिनी कारोबार में चार फीसद तक लुढ़के। कोरोना के प्रसार को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां 2020 के लिए वैश्विक विकास दर के अनुमान 3.5-4 फीसद में एक फीसद की गिरावट की बात करने लगी हैं। मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर के वैश्विक सप्लाई चेन के अस्त-व्यस्त होने के साथ ही पर्यटन, होटल जैसे क्षेत्र पर भी मंदी के असर की बात कही जा रही है।

विदेशी संस्थागत निवेशक पहले से ही अपना निवेश खींच रहे हैं पेज>>12

बीएसई की दुर्गति

- 2,011 कंपनियां हुईं गिरावट का शिकार
- 437 कंपनियों के स्टॉक्स 52 सप्ताह के निचले स्तर तक लुढ़के
- 106 कंपनियों के स्टॉक्स में लोअर सर्किट लगा
- 1,46,93,797.43 करोड़ रुपये रह गया बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल पूंजीकरण

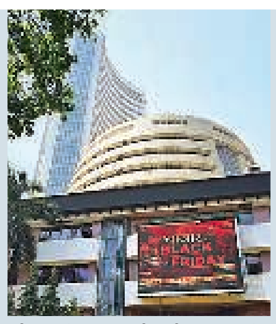

बीएसई के बाहर लगी स्क्रीन। प्रेट्र

- पिछले 11 वर्षों में सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट का शिकार हुआ सेंसेक्स
- दुनियाभर के शेयर बाजारों पर कोरोना का आतंक, बच नहीं पाए घरेलू बाजार

सेंसेक्स की पांच बड़ी गिरावट

24 अगस्त, 2015	1,624
28 फरवरी, 2020	1,448
21 जनवरी, 2008	1,408
24 अक्टूबर, 2008	1,070
01 फरवरी, 2020	988

ग्लोबल शेयर बाजारों की हालत

बाजार	गिरावट (अंक)	बदलाव (प्रतिशत)
नास्दैक	414	4.61
निक्केई	803	4.02
एफटीएसई	246	3.49
शंघाई	100.77	3.37
डैक्स	407	3.19
हैंगसैंग	670	2.50

सेक्टोरल इंडेक्स का यह हाल
बीएसई के किसी भी सेक्टोरल इंडेक्स को राहत नहीं मिली। सबसे ज्यादा 7.01 प्रतिशत की गिरावट मेटल इंडेक्स में दर्ज की गई, आइटी, बेसिक मैटीरियल्स, टेक, इंडस्ट्रियल्स, रियल्टी, कैपिटल गुड्स, ऑटो व फाइनेंस भी 3.71 प्रतिशत तक गिर गए। बीएसई स्मॉल कैप में 3.52 और मिडकैप में 3.13 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

चार सौ दिन बाद कन्हैया पर देशद्रोह के केस की मंजूरी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने के मामले में दिल्ली सरकार ने लिया फैसला

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में देश विरोधी नारे लगाने के मामले में शुक्रवार को दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 13 माह (400 दिन) बाद जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार समेत दस अन्य के खिलाफ देशद्रोह का मामला चलाने के लिए पुलिस को अनुमति दे दी है। पुलिस की स्पेशल सेल ने मामले की जांच की थी, लेकिन राज्य सरकार के अनुमति नहीं देने के कारण वह चार्जशीट दाखिल नहीं कर पा रही थी।

नौ फरवरी 2016 को जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने के वीडियो सामने आए थे, इसके बाद मामले की जांच की गई। कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्या, आकिब हुसैन, मुजीब हुसैन, मुनीब हुसैन, उतर गुल, रईस रसूल, बसरत अली व खालिद बशीर भट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत में 14 जनवरी 2019 को आरोपपत्र भी दाखिल किया गया, मगर दिल्ली सरकार ने देश द्रोह के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी थी। सरकार ने उस समय कहा था कि दिल्ली पुलिस ने नियमों का उल्लंघन किया है। उससे बगैर अनुमति के आरोपपत्र दाखिल किया गया है।

पुलिस को कई बार लगी फटकार

इस मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी न मिलने के कारण पुलिस को अदालत से कई बार फटकार लगी। पिछले साल 14 जनवरी को दायर किए गए आरोपपत्र पर अदालत ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया, क्योंकि पुलिस को राज्य सरकार से मंजूरी नहीं मिल रही थी। बार-बार सुनवाई टलती रही और हर बार पुलिस का यही जवाब होता था कि मंजूरी नहीं मिली। गत 19 फरवरी को अदालत ने कहा था कि सरकार को फिर से पत्र लिखकर मंजूरी लें और 3 अप्रैल तक रिपोर्ट दाखिल करें।

बाद में दिल्ली सरकार ने कहा था कि कानूनी राय ली जा रही है। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने इस मामले को उछाला था और आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की थी। जिस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में जल्द कार्रवाई के संकेत दिए थे। (पेज-2 भी देखें)

तीसरी तिमाही में 4.7 फीसद रही विकास दर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कोरोना वायरस की वजह से आर्थिक चुनौतियों के बढ़ने की आशंका के बीच अर्थव्यवस्था की स्थिति बताने वाली ताजी तस्वीर बहुत उत्साहवर्धक नहीं है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर, 2019) में आर्थिक विकास दर 4.7 फीसद रही है, जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह वृद्धि दर 5.6 फीसद रही थी। सरकार ने एक दूसरा आंकड़ा बुनियादी क्षेत्र को लेकर दिया है जिसके मुताबिक जनवरी, 2020 में देश के आठ प्रमुख बुनियादी औद्योगिक सेक्टरों की संयुक्त वृद्धि दर 2.2 फीसद रही है और अप्रैल-जनवरी के दौरान बड़े पैमाने पर रोजगार देने वाले इन उद्योगों में सिर्फ 0.6 फीसद की ही वृद्धि रही है। तीसरा आंकड़ा सरकार के राजकोषीय हालात को लेकर है जो बताता है कि जनवरी, 2020 तक राजकोषीय घाटा पूरे साल के लक्ष्य का 128.5 फीसद पर पहुंच चुका है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) की तरफ से शुक्रवार को जारी सूचना के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के दौरान देश की आर्थिक विकास दर पांच फीसद रहेगी जबकि पिछले वित्त वर्ष के दौरान यह दर 6.1 फीसदी थी। अगर यह अनुमान सही साबित हो जाता है तो यह पिछले 11 वर्षों की सबसे बड़ी गिरावट होगी।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जुलाई से सितंबर की तिमाही की विकास दर के पहले लगाए गए अनुमान को 4.5 फीसद से बढ़ाकर 5.1 फीसद किया है। इसके बावजूद पूरे वित्त वर्ष के पूर्वानुमान में कोई बदलाव इसलिए नहीं किया गया है कि जनवरी-मार्च, 2020 की तिमाही पर कोरोना वायरस का असर आने की आशंका है। वैसे इस तिमाही में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर 3.9 फीसद रही है जो पिछले वर्ष 5.1 फीसद रही थी।

बेहतर मानसून का असर कृषि सेक्टर पर दिखाई दिया है पेज>>12

सरकार के आंकड़े

- अक्टूबर-दिसंबर, 19 में 4.7 फीसद रही अर्थव्यवस्था की रफ्तार
- आठ बुनियादी उद्योगों की विकास दर 0.6 फीसद पर सिमटी
- जनवरी, 20 तक राजकोषीय घाटा लक्ष्य का 128 फीसद तक पहुंचा
- प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर 5.1 फीसद से घट कर 3.9 फीसद पर आई

उत्तराखंड में 35 वर्षों से हर शनिवार को वकीलों की हड़ताल गैरकानूनी : कोर्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार के तहत हड़ताल न्यायोचित नहीं

देश के विभिन्न हिस्सों में आए दिन होने वाली वकीलों की हड़ताल पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। शीर्ष कोर्ट ने उत्तराखंड के तीन जिलों देहरादून, हरिद्वार व ऊधमसिंह नगर में 35 वर्षों से हर शनिवार को होने वाली वकीलों की हड़ताल को गैरकानूनी करार दिया है। कोर्ट ने कहा, अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार (अनुच्छेद 19-1-ए) की आड़ में हड़ताल व अदालतों के बहिष्कार को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। हाई कोर्ट ने भी इस हड़ताल को गैरकानूनी ठहराया था। शीर्ष अदालत ने कहा, हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। आदेश का उल्लंघन कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी और उससे सख्ती से निपटा जाएगा।

वकीलों की हड़ताल को गैरकानूनी ठहराने के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 29 सितंबर, 2002 के प्रस्ताव के बावजूद देश के विभिन्न हिस्सों में आए दिन होने वाली वकीलों की हड़ताल पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जस्टिस अरुण मिश्रा और एमआर शाह की पीठ ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया और राज्य बार काउंसिलों को नोटिस जारी कर इस पर अंकुश लगाने के लिए छह हफ्तों के भीतर पुख्ता सुझाव देने को कहा है।

उत्तराखंड हाई कोर्ट के 25 सितंबर, 2019 के फैसले को चुनौती देने वाली देहरादून बार एसोसिएशन की याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहले भी शीर्ष कोर्ट अपने फैसलों में कह चुका है कि त्वरित न्याय अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) व अनुच्छेद 21 (स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार) का हिस्सा है। कृष्णकांत ताम्रकर केस में कोर्ट कह चुका है-मुकदमों में देरी का एक कारण वकीलों की बेवजह की हड़ताल भी है।

विधि आयोग की रिपोर्ट में भी यही बात पेज>>4

सावधानी

भारत की मदद से अफगानिस्तान में चल रही हैं 500 से ज्यादा परियोजनाएं, समझौते से पहले काबुल पहुंचे विदेश सचिव श्रृंगला, पाकिस्तान परस्त तालिबान भारत के लिए चिंता का कारण

अमेरिका-तालिबान समझौते पर भारत की सतर्क नजर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अफगानिस्तान में शांति बहाली के लिए अमेरिका-तालिबान में शनिवार को ऐतिहासिक समझौता होना है। वर्षों से हिंसा, रक्तपात और अस्थिरता के दौर से गुजर रहे अफगानिस्तान में इससे अमन चैन कायम होने की उम्मीद है, लेकिन इससे काबुल में तालिबान के आने का रास्ता भी खुल जाएगा। यही भारत के लिए चिंता का विषय है। पहली चिंता यह है कि पाक परस्त तालिबान कहीं फिर से भारत विरोधी गतिविधियों का केंद्र न बन जाए। दूसरा अफगानिस्तान में अरबों डॉलर की सैकड़ों परियोजनाएं अधर में न लटक जाएं।

इन चिंताओं के बीच शुक्रवार को काबुल पहुंचे विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी, सीईओ अब्दुल्ला अब्दुल्ला, निर्वाचित उप राष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमदुल्ला मोहिब और विदेश मंत्री हारून चखनसूरी से भेंट की। उन्होंने गनी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्र भी सौंपा।

हर्षवर्धन श्रृंगला (चश्मा पहने हुए) प्रेट्र

भारत ने फिर स्पष्ट किया है कि किसी भी शांति समझौते में अफगानी जनता और उसके द्वारा चुनी गई सरकार की पूरी भागीदारी और सत्ता की चाबी निर्वाचित सरकार के पास रहनी चाहिए। अमेरिका-तालिबान के बीच समझौते से अफगानिस्तान में नई सरकार के गठन का रास्ता भी साफ होगा और अमेरिकी सैनिकों की 18 साल बाद घर वापसी शुरू होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गत सोमवार को दिल्ली में कहा था कि वह अब अफगानिस्तान में पुलिस की भूमिका निभाने को तैयार नहीं हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने एक के बाद एक ट्वीट कर बताया कि श्रृंगला के साथ बैठक में गनी ने अफगानिस्तान में लोकतंत्र व संवैधानिक व्यवस्था बनाए रखने में भारत के सतत समर्थन की सराहना की।

इससे पहले दिन में रवीश कुमार ने कहा था, 'विदेश सचिव श्रृंगला और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के बीच हुई मुलाकात में द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की गई है। विदेश सचिव ने भारत की तरफ से यह आश्वस्त किया कि अफगानिस्तान में स्थायी शांति, सुरक्षा व विकास के लिए वहां की जनता को हमेशा मदद दी जाती रहेगी।'

श्रृंगला की अफगानिस्तान के शीर्ष नेताओं के साथ भारत की मदद से चलाई जा रही परियोजनाओं के भविष्य पर भी चर्चा हुई। भारत डेढ़ दशक से वहां कई बड़ी परियोजनाओं (संसद भवन का निर्माण, बिजली बनाने व सिंचाई करने के लिए बांध आदि) समेत कई छोटी-छोटी परियोजनाओं (स्कूलों, पुलों, अस्पतालों आदि का निर्माण) का काम कर रहा है। साथ ही सॉफ्ट डिप्लोमेसी के तहत अफगानिस्तान में खेल व संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए काफी मदद की है।

ज्ञात हो, भारत अभी अफगानिस्तान में 500 से ज्यादा छोटी बड़ी परियोजनाएं चला रहा है। तीन अरब डॉलर (लगभग 21 हजार करोड़ रुपये) की परियोजनाएं पूरी कर चुका है। इतनी राशि की और परियोजनाओं पर विमर्श हो रहा था। अभी तक भारत की चिंताओं को लेकर किसी भी पक्ष ने कोई बयान नहीं दिया है।

नई दिल्ली दौरे पर ट्रंप ने कहा था, पीएम मोदी से अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा की थी और उन्होंने खुशी जताई थी। ट्रंप के बयान के बावजूद तालिबान का अफगानिस्तान सरकार में शामिल होना ही भारत के लिए एक चिंताजनक खबर है। तालिबान का जो धड़ा अमेरिका से शांति वार्ता कर रहा है वह पूरी तरह से पाकिस्तान के संपर्क में है। पाकिस्तान पूर्व में इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर चुका है। (पेज-13 भी देखें)

मुस्लिमों को आरक्षण पर महाराष्ट्र के दो मंत्री आमने-सामने

राज्य ब्यूरो, मुंबई

- राकांपा कोटे के मंत्री नवाब मलिक ने कहा, पांच फीसद आरक्षण देगी सरकार
- शिवसेना कोटे के वरिष्ठ मंत्री एकनाथ शिंदे बोले, अभी कोई फैसला नहीं हुआ

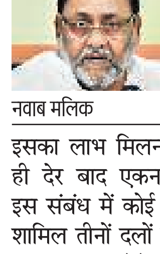

नवाब मलिक

एकनाथ शिंदे (फाइल)

मुस्लिमों को शिक्षा एवं नौकरियों में पांच फीसद आरक्षण देने के मुद्दे पर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार के दो घटक दल शिवसेना व राकांपा में मतभेद नजर आ रहे हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने अगले शैक्षणिक सत्र से मुस्लिमों के लिए कोटा लागू करने की बात कही है। वहीं, शिवसेना कोटे के वरिष्ठ मंत्री एकनाथ शिंदे का कहना है कि इस तरह के नीतिगत मुद्दे पर अभी कोई भी फैसला नहीं हुआ है।

विधान परिषद में शुक्रवार को कांग्रेस सदस्य शरद रणपिसे के सवाल का जवाब देते हुए राकांपा कोटे से मंत्री मलिक ने कहा, सरकार मुस्लिमों को शिक्षा एवं नौकरियों में पांच फीसद आरक्षण देने पर विचार कर रही है। सरकार इस आशय का कानून जल्द बनाने की कोशिश करेगी, ताकि अगले शैक्षणिक सत्र से छात्रों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाए। कुछ ही देर बाद एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस संबंध में कोई भी फैसला सरकार में शामिल तीनों दलों से चर्चा के बाद लिया जाएगा। इस संबंध में सीएम उद्धव ठाकरे उचित समय पर उचित फैसला लेंगे।

शिवसेना ने लिया था मुस्लिमों को आरक्षण देने का पक्ष पेज>>4